

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि दुनिया भारत पर भरोसा करती है और भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में यशोभूमि में आज सेमीकॉन इंडिया दो हजार पचीस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया में सबसे बड़ा परिवर्तन लाएगी।

21वीं शताब्दी की शक्ति छोटे से चिप में सिमट करके रह गई है। यह चिप भले ही छोटी सी है लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को बड़ी गति देने की ताकत है और इसलिए ही आज सेमीकंडक्टर का ग्लोबल मार्केट 600 बिलियन डॉलर पर पहुंच रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार एक ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाएगा और जिस गति से भारत आगे बढ़ रहा है, उससे देश इस बाजार में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हासिल कर लेगा। उन्होंने पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़ों के बारे में कहा कि भारत ने एक बार फिर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है।

एक तरफ जब दुनिया भर की इकॉनमीज में चिंताएं हैं। आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियां हैं। उस माहौल में भारत में 7.8: की ग्रोथ हासिल करके दिखाई है और यह ग्रोथ हर सेक्टर में है। हर तरफ उत्साह नजर आ रहा है।

इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत के बाद से विश्व पूरे विश्वास के साथ भारत की ओर देख रहा है। इस समय देश में पांच सेमीकंडक्टर इकाइयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में आज लोकहित के कुल पंद्रह प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई। एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत बैठक में कम्पनीज एक्ट-दो हजार तेरह के सेक्शन-आठ के अंतर्गत उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन को मंजूरी दी गई है। यह एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी होगी, जिसे नॉन-प्रॉफिटेबल संस्था के रूप में संचालित किया जाएगा। एक रिपोर्ट-

प्रदेश में आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन अब सीधे विभाग नहीं करेंगे। इन एजेंसियों का चयन अब उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड जेम पोर्टल के माध्यम से करेगा। आउटसोर्स कर्मचारियों का चयन तीन वर्षों के लिए किया जाएगा। कर्मचारियों के लिए कम से कम सोलह से बीस हजार रुपये का मानदेय निर्धारित किया गया है। आउटसोर्स कर्मचारियों से महीने में छब्बीस दिन सेवा ली जा सकेगी। उनका वेतन एक से पांच तारीख तक उनके खाते में आ जाएगा। ईपीएफ और ईएसआई का अंशदान अब सीधे कर्मचारियों के खाते में जाएगा। वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था की अनियमितताओं को खत्म करने और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए ही निगम का गठन किया गया है। समाचार कक्ष से प्रेम चन्द्र गुप्ता।

कैबिनेट के अन्य फैसलों में कानपुर और लखनऊ में नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर ई-बसों का संचालन, निर्यात प्रोत्साहन नीति दो हजार पचीस-तीस को मंजूरी और शाहजहांपुर जिले में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्वीकृति प्रमुख तौर पर शामिल हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, अद्वारह सौ साठ के स्थान पर प्रदेश में नया कानून लागू किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। कल लखनऊ स्थित अपने आवास पर आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि सोसाइटी के रूप में पंजीकृत संस्थाओं के पंजीकरण, नवीनीकरण तथा उनकी संपत्तियों के पारदर्शी प्रबन्धन को सुदृढ़ करने के लिए युगानुकूल और व्यावहारिक प्राविधान किए जाने चाहिए।

भूतान के प्रधानमंत्री दाशो शेरींग टोबगे पांच सितम्बर को अयोध्या दौरे पर आएंगे। उनके दौरे को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसे देखते हुए अयोध्या के जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे और एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने रामजन्मभूमि परिसर और अन्य प्रमुख स्थलों का निरीक्षण किया।

प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश का क्रम जारी है। अत्यधिक बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए आज पीलीभीत और रायबरेली सहित कई अन्य जिलों में स्कूलों को बंद रखा गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, वाराणसी और जौनपुर जिलों में भी आज हल्की से लेकर तेज वर्षा हुई।

लगातार हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियां उफान पर हैं। इस समय बलिया, प्रयागराज, वाराणसी और बदायूं सहित सत्रह जिलों के दो लाख पचास हजार से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। हालात को देखते हुए राज्य में बाढ़ राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। इस बीच, मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों में भी कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और वर्षा की संभावना जताई है।
